आवास विभाग के ईज एप को केंद्र ने सराहा, पत्रिका में मिला स्थान

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड आवास विभाग के नागरिक केंद्रीयत आनलाइन ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन ईज एप को केंद्र ने भी सराहा है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन लोक शिकायत और पेंशन विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की व्यवस्था पर जोर देता है। इसी क्रम में देशभर में होने वाली विशेष पहल को विभाग अपनी अर्द्धवार्षिक ई-पत्रिका में स्थान देता है। ईज एप की पहल को भी पत्रिका में स्थान मिला है।

ईज एप के माध्यम से राज्य के सभी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों और नागरिकों को मानचित्र स्वीकृति, परियोजना प्रबंधन, शिकायत निवारण, सूचना डाक व पत्रावली प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे आंतरिक व बाह्य कार्यों का संचालन किया जाता है। राज्य स्तर पर उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को इसके संचालन, रखरखाव व प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है।

यह एप्लीकेशन आनलाइन भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे से एकीकृत है। एयरपोर्ट अथारिटी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र और भूमि की जियोलोकेशन के लिए भी इसका एकीकरण किया गया है।